उच्च न्यायालय, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

रिट याचिका संख्या 84/2004

याचिकाकर्ता:

अजीत प्रमोद कुमार जोगी,
आयु- लगभग 58
पुत्र स्वर्गीय के.पी. जोगी, निवासी
करुणा सिविल लाइंस,
जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

बनाम

उत्तरवादी:

1. भारत संघ, सचिव, गृह मंत्रालय ,
भारत सरकार, नई दिल्ली

2. निदेशक, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो,
सीजीओ कॉम्प्लेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली

3. अधीक्षक, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो,
जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

4. छत्तीसगढ़ राज्य, गृह सचिव,
छत्तीसगढ़ सरकार, जिला रायपुर

5. अधीक्षक, राज्य भ्रष्टाचार निरोधक
कार्यालय, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

.....

निर्णय दिनांक : 6 फरवरी, 2004

सही /-
न्यायाधीश एल.सी भादू,

उच्च न्यायालय, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

रिट याचिका संख्या 84/2004

याचिकाकर्ता:

अजीत प्रमोद कुमार जोगी,
आयु- लगभग 58
पुत्र स्वर्गीय के.पी. जोगी,
निवासी
करुणा सिविल लाइंस,
जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

बनाम

उत्तरवादी:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. भारत संघ, सचिव, गृह मंत्रालय ,
   भारत सरकार, नई दिल्ली

2. निदेशक, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो,
   सीजीओ कॉम्प्लेक्स,
   लोधी रोड, नई दिल्ली

3. अधीक्षक, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो,
   जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

4. छत्तीसगढ़ राज्य, गृह सचिव,
   छत्तीसगढ़ सरकार, जिला रायपुर

5. अधीक्षक, राज्य भ्रष्टाचार निरोधक
   कार्यालय, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

उपस्थित:

याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित हैं

श्री राजेंद्र सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री विवेक तन्खा, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री वी.डी. बाजपेयी, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री धीरेंद्र मिश्रा, अधिवक्ता, श्री अतुल शांडिल्य, अधिवक्ता, श्री अमित श्रीवास्तव, अधिवक्ता और श्री विवेक शर्मा, अधिवक्ता

भारत संघ/विपक्षी संख्या 1, 2 और 3 की ओर से
श्री विनय हरित, वरिष्ठ केंद्रीय सरकार स्थायी अधिवक्ता, श्री रामाकांत मिश्रा, अतिरिक्त स्थायी अधिवक्ता,
राज्य की ओर से उपस्थित हैं
श्री रविश अग्रवाल, महाधिवक्ता, श्री सुनील सिन्हा, अतिरिक्त महाधिवक्ता और श्री संजय के. अग्रवाल, उप महाधिवक्ता
हस्तक्षेपकर्ता की ओर से श्री प्रशांत मिश्रा, अधिवक्ता उपस्थित हैं।

आदेश
(6 फरवरी, 2004 को पारित)

एल.सी. भादू, न्यायाधीश के अनुसार।

याचिकाकर्ता जो छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ने भारत के संविधान की अनुच्छेद 226/227 के तहत यह रिट याचिका दायर की है, जिसके तहत उन्होंने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7, 12, 13 (1) (घ), 13 (2) और 15 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 120-ख और धारा 34 के तहत अपराध करने के लिए दिनांक 9-12-2003 को दर्ज प्र.सु.प्र. आर सी 7(ए)/2003 की वैधता, शुद्धता और प्रामाणिकता को चुनौती दी है और इस आधार पर इसे रद्द करने की मांग की है कि इसमें आगे की विवेचना और विवेचना के लिए कोई संज्ञेय अपराध प्रकट नहीं होता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. इस याचिका को दायर करने के पीछे संक्षिप्त तथ्य यह है कि छत्तीसगढ़ राज्य की विधान सभा के लिए आम चुनाव 1 दिसंबर 2003 को आयोजित किए गए थे और इसके परिणाम 4 दिसंबर 2003 को घोषित किए गए थे। उस समय याचिकाकर्ता मुख्यमंत्री थे और 7 दिसंबर 2003 को नए मुख्यमंत्री के पदभार ग्रहण करने तक याचिकाकर्ता कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे थे। 4 दिसम्बर 2003 को परिणाम घोषित होने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 37 सीटें हासिल की भारतीय जनता पार्टी ने 50 सीटें हासिल की ब.स.पा. ने 2 सीटें हासिल की और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने 1 सीट हासिल की।

3. प्रथम सूचना रिपोर्ट (अनुलग्नक-R/1) के अनुसार, जो 7-12-2003 को रात 2 बजे पुलिस स्टेशन, एंटी करप्शन ब्यूरो, रायपुर में श्री विरेंद्र पांडे द्वारा दर्ज कराई थी, कार्यवाहक मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी, उनके पुत्र अमित जोगी और सांसद श्री बी.आर. खूंटे ने भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों को 45 लाख रुपए की रिश्वत देकर तोड़ने की आपराधिक षडयंत्र रची तथा इस षडयंत्र के अग्रसण मे 5-12-2003 को दोपहर में उन्हें श्री बी.आर. खूंटे का फोन आया कि अगर प्रयास किए जाएं तो श्री बलिराम कश्यप मुख्यमंत्री बन सकते हैं और इस संबंध में श्री अजीत जोगी भी मदद कर सकते हैं। जब उन्होंने श्री खूंटे से पूछा कि यह कैसे संभव है, तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर नए भाजपा विधायकों में से छह विधायक पार्टी तोड़ दें तो श्री अजीत जोगी उन विधायकों को 37 कांग्रेस विधायकों, 2 बसपा विधायकों और एक राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के विधायक का समर्थन सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने उन्हें दो घंटे बाद फोन करने को कहा और दो घंटे बाद श्री खूंटे ने फिर से फोन किया। उन्होंने फिर से श्री खूंटे से रात में फोन करने को कहा, लेकिन उन्होंने रात में फोन करने में असमर्थता व्यक्त की और कहा कि वह सुबह फोन करेंगे। इस बीच, उन्होंने अपने टेलीफोन नंबर 2442766 पर आवाज-रिकॉर्डिंग उपकरण लगा दिए और जब सुबह श्री खूंटे ने उन्हें फोन किया, तो उनकी बातचीत रिकॉर्ड की गई। उनकी बातचीत से उन्हें पता चला कि उन्होंने कुछ भाजपा विधायकों को रिश्वत देकर तोड़ने की षडयंत्र रची है ताकि उन विधायकों के समर्थन से बलिराम कश्यप को मुख्यमंत्री बनाया जा सके। इस संबंध में श्री खूंटे ने उन्हें श्री अजीत जोगी का समर्थन आश्वस्त किया। इसके बाद श्री जोगी ने भी उन्हें उसी नंबर पर फोन किया और उनकी बातचीत भी रिकॉर्ड की गई। फोन पर हुई बातचीत में श्री जोगी ने उन्हें राजनीतिक और वित्तीय मदद का आश्वासन दिया और कहा कि वह श्री खूंटे के माध्यम से 15-20 लाख रुपए भेजेंगे। इसके बाद दो घंटे बाद श्री खूंटे ने उन्हें फोन किया और बताया कि 20 लाख रुपए पहुंच गए हैं और वह अपने बेटे बंटी के साथ भेज रहे हैं। जब वह माइनिंग विभाग की इमारत के पास पहुंचे तो उन्होंने अपने टेलीफोन नंबर 5031201 से

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

फोन किया और कुछ देर बाद बंटी एक एम्बेसडर कार में आया और कार की पिछली सीट पर दो बैग थे, एक काले रंग का और दूसरा सफेद। उन बैगों को उनके ड्राइवर ने लिया और अपनी गाड़ी में रख लिया। इसके बाद उन्होंने पैसे मिलने की जानकारी केंद्रीय नेताओं को दी और कैसेट पर रिकॉर्ड हुई बातचीत के बारे में बताया। उन्होंने उन्हें आगे बढ़ने की सलाह दी। इसके बाद वह लगातार श्री खूंटे के साथ टेलीफोन पर संपर्क में रहे और उन्होंने श्री खूंटे को बताया कि श्री बलिराम कश्यप शाम 7-8 बजे आएंगे और उनके आने पर श्री जोगी के साथ बैठक का कार्यक्रम तय किया जाएगा। शाम 7 बजे बलिराम कश्यप उनके पास आए और उन्होंने बताया कि रास्ते में उनकी श्री जोगी से बात हुई थी और श्री जोगी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनने में मदद करने का आश्वासन दिया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. श्री बलिराम कश्यप ने उन्हें बताया कि रायपुर पहुंचने के बाद वह श्री जोगी से बात करेंगे। इसके बाद उन्होंने श्री जोगी से बात की और श्री जोगी ने उन्हें बताया कि श्री सोम प्रकाश गिरि बताएंगे कि वे कहां मिलेंगे और अंततः यह तय हुआ कि वे रेडिएंट स्कूल के पास एकांत स्थान पर मिलेंगे। श्री जोगी ने बताया कि श्री सोम प्रकाश गिरि उनके साथ होंगे जो भगत सिंह चौक पर मिलेंगे। रात लगभग 8-9 बजे वह बलिराम कश्यप, श्री सोम प्रकाश गिरि, श्री कश्यप के अंगरक्षक और उनके ड्राइवर के साथ बलिराम कश्यप की स्कॉर्पियो गाड़ी से रवाना हुए। कुछ समय बाद गाड़ी को उपरवारा रोड पर खड़ा कर दिया गया। इसके बाद एक कार पीछे से आई, रुकी और आगे बढ़ गई। 15-20 मिनट बाद एक टाटा सफारी, काले रंग की कार, बिना नंबर की, आई और वह कार भी आगे बढ़ गई। उस कार में श्री जोगी थे। वह कार कुछ दूरी पर रुकी और वह बलिराम कश्यप और सोम प्रकाश गिरि के साथ उस कार में सवार हुए और श्री जोगी के साथ पिछली सीट पर बैठ गए और गाड़ी में बातचीत हुई। बातचीत के दौरान श्री जोगी ने समर्थन का पत्र दिया। उनका गाड़ी श्री जोगी के गाड़ी का पीछा कर रहा था और वापस आते समय श्री जोगी ने कार रोकी और वे कार

से उतर गए। उस समय श्री जोगी का एक परिचित लड़का दूसरी गाड़ी में आया और अमित जोगी के पास आया, जिसे उसने कहा कि आपके कार में रखे सामान उन्हें दे दें और वह सामान 25 लाख रुपए था। वह लड़का उनके गाड़ी में बैठ गया और श्री जोगी की गाड़ी वहां से चली गई। वह बलिराम कश्यप और उस लड़के के साथ अपने गाड़ी में रवाना हुए और उपरवारा टर्न पर एक सफेद रंग की कार बिना नंबर की खड़ी थी, जिसके पास लड़के ने गाड़ी रोक दी और एक नीला बैग जो पीछे की तरफ रखा था, उसके बारे में उसने कहा कि इस बैग में 25 लाख रुपए हैं और श्री जोगी ने श्री गिरि को वहीं छोड़ दिया। वह उनके वाहन में बैठ गए। वे काली कार छोड़कर सीधे कार्यालय आए जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। चूंकि उनके पास 45 लाख रूपए थे, इसलिए सुरक्षा का सवाल था, इसलिए उन्होंने इस तथ्य का खुलासा कॉन्फ्रेंस में किया और इसी कारण वह इस रिपोर्ट के साथ नकद राशि, कैसेट और श्री जोगी का पत्र जो महामहिम राज्यपाल को संबोधित है, जमा कर रहे हैं। श्री जोगी, जो एक लोक सेवक हैं, ने श्री खूंटे के साथ मिलकर राजनीतिक समर्थन के लिए रिश्वत की व्यवस्था की।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. इस रिपोर्ट को प्राप्त करने के बाद, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, छत्तीसगढ़, रायपुर ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धाराओं 13(1)(घ), 13(2)/12 और 15 और भारतीय दंड संहिता की धाराओं 34 और 120-ख के तहत प्र.सु.प्र. दर्ज की। इसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति अधिसूचना दिनांक 8 दिसंबर, 2003 के अनुसरण में, कैबिनेट सचिवालय, भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना दिनांक 9-12-2003 के माध्यम से मामले की विवेचना प्र.सु.प्र. संख्या 9/2003 दिनांक 7-12-2003 को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को हस्तांतरित कर दी।

6. याचिका के कंडिका 5.2 में किए गए कथन के अनुसार, यह उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता शुरू से ही उनके और अन्य के खिलाफ दर्ज की गई कथित प्र.सु.प्र. की प्रामाणिकता और शुद्धता से इनकार करता है और रिपोर्ट को चुनौती देना चाहता है क्योंकि यह आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार आगे की विवेचना/तहकीकात या मुकदमे की वारंटी देने वाला कोई संज्ञेय अपराध प्रकट नहीं करती है। यह उल्लेख किया गया है कि तथ्य उक्त धाराओं के तहत अपराधों के आयोग को प्रकट नहीं करते हैं। यह आगे उल्लेख किया गया है कि श्री जोगी, उनके पुत्र अमित जोगी, श्री खूंटे स्वयं श्री विरेंद्र पांडे और बलिराम कश्यप की वास्तविक भागीदारी के बिना किसी अवैध कृत्य को अंजाम देने या अवैध साधनों का उपयोग करने के लिए षड्यंत्र नहीं कर सकते थे। याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया कि उनका कथित नए निर्वाचित भाजपा विधायकों से कोई संपर्क नहीं था, और न ही याचिकाकर्ता द्वारा इन विधायकों तक पहुंचने का कोई प्रयास किया गया था, चाहे वह खुले या गुप्त तरीके से हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. श्री विरेंद्र पांडे, बलिराम कश्यप और याचिकाकर्ता के बीच आपराधिक षडयंत्र की अनुपस्थिति में, ऐसा कोई कथित अपराधिक योजना नहीं बनाई जा सकती थी, प्रयास नहीं किया जा सकता था या अंततः अंजाम नहीं दिया जा सकता था। प्र.सु.प्र. में ऐसी कोई सहमति प्रकट नहीं होती है और वास्तव में यह किसी नियंत्रित नाटक की सूचना देता है की जानकारी होती है। एक प्रेरित या मंचित अपराध की शिकायत को आपराधिक षडयंत्र के अपराध के प्राथमिक तत्वों के रूप में नहीं बनाया जा सकता है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7/11 के साथ धारा 12 के मूल तत्व निर्मित करने हेतु धारा 7/11 के तहत मूल अपराध कारित करने का षडयंत्र आवश्यक था। किसी भी समय शिकायतकर्ता, अर्थात् विरेंद्र पांडे और बलिराम कश्यप, याचिकाकर्ता और कुछ अन्य लोगों के साथ आपराधिक षडयंत्र में नहीं थे। वास्तव में, शिकायत के अनुसार, याचिकाकर्ता के साथ धोखाधड़ी की गई थी।

विधि में, याचिकाकर्ता शिकायतकर्ता की चाल के कथित और अवैध जाल में फंसकर कथित अपराध नहीं कर सकता है।

8. किसी भी ऐसी प्र.सु.प्र. की सामग्री भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7/11 के साथ धारा 12 के तहत एक प्रथम दृष्टया अपराध के तत्वों को भी पूर्ण नहीं करेगी। प्र.सु.प्र. में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(घ), 13(2) के साथ धारा 15 के संज्ञेय अपराध के मूल तथ्यों और मूल तत्वों का खुलासा नहीं होता है। अंततः, यह प्रार्थना की गई है कि उत्तरवादीओं को प्र.सु.प्र., केस डायरी और मामले से संबंधित रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया जाए और उत्प्रेषण की रिट या कोई अन्य उपयुक्त रिट या निर्देश जारी करके श्री विरेंद्र पांडे द्वारा दर्ज की गई 5/6 नवंबर 2003 की प्र.सु.प्र. को रद्द किया जाए, क्योंकि इसमें कोई अपराध प्रकट नहीं होता है और इसके परिणामस्वरूप दिल्ली पुलिस स्थापना अधिनियम के प्रावधानों के तहत आगे की विवेचना की कोई आवश्यकता नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. उत्तरवादीओं 1 से 3 की ओर से आपत्तियों का प्रारंभिक उत्तर दायर किया गया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि उत्तरवादी संख्या 2 और 3 देश की प्रमुख अपराध विवेचना एजेंसी के जिम्मेदार अधिकारी हैं। इस विवेचना एजेंसी की प्रतिष्ठा एक पूरी तरह से पेशेवर, निष्पक्ष और सक्षम एजेंसी के रूप में आम ज्ञान है और आम जनता का उच्चतम स्तर का विश्वास कमांड करती है, जिसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। यह आगे उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा इस न्यायालय के अवलोकन के लिए मांगे गए दस्तावेज अत्यधिक वर्गीकृत प्रकृति के हैं क्योंकि अपराध की गंभीरता और इसमें अत्यधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की भागीदारी की संभावना को देखते हुए, जब इस मामले की विवेचना लगातार चल रही है, उत्तरवादीओं की विवेचना और निष्कर्षों का थोड़ा सा भी रिसाव न्याय के कारण को अत्यधिक नुकसान पहुंचा सकता है। याचिकाकर्ता ने अपने दावों के समर्थन में कोई विधिक रूप से टिकाऊ आधार

नहीं बताया है कि प्र.सु.प्र. में प्रथम दृष्टया कार्रवाई का कोई कारण नहीं है। प्र.सु.प्र. में उन अपराधों के सभी तत्व शामिल हैं जो शिकायतकर्ता द्वारा किए गए हैं और विधि के अनुसार विवेचना के साथ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार हैं। जब तक विवेचना पूरी नहीं हो जाती है और इसके परिणाम का निपटारा नहीं हो जाता है, तब तक इस स्तर पर बिना किसी आधार के अटकलें लगाना या आशंकाएं व्यक्त करना बहुत जल्दबाजी होगी। यदि विवेचना पूरी होने के बाद उत्तरवादी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि याचिकाकर्ता या किसी भी संदिग्ध के खिलाफ कथित अपराधों के तत्व नहीं हैं, तो उत्तरवादी अपनी रिपोर्ट तदनुसार प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होंगे।

10. यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि यदि विवेचना पूरी होने के बाद उत्तरवादी इस राय पर पहुंचते हैं कि अपराध किया गया है और किसी या सभी संदिग्धों के खिलाफ आगे बढ़ने के आधार हैं, तो उनके द्वारा तैयार की गई अंतिम रिपोर्ट को विधि के प्रावधानों के अनुसार न्यायिक विवेचना से गुजरना होगा। याचिकाकर्ता द.प्र.सं. की धारा 482 के तहत आवेदन कर सकता था और ऐसा न करके वह इस न्यायालय के असाधारण रिट क्षेत्राधिकार को लागू कराने का प्रयास कर रहा है। याचिकाकर्ता का आशय वास्तविक नहीं लगता है क्योंकि वह विवेचना से संबंधित दस्तावेजों को सार्वजनिक करने का प्रयास कर रहा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. उत्तरवादीओं 4 और 5 की ओर से भी इसी प्रभाव के लिए जवाब दायर किया गया है।

12. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है।

13. जहां तक इस याचिका की भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत सुनवाई की पोषणीयता का संबंध है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **1998**

सुप्रीम कोर्ट 128 में प्रतिवेदित **मेसर्स पेप्सी फूड्स लिमिटेड व अन्य बनाम विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट व अन्य** मामले में यह निर्णय दिया है,

"उच्च न्यायालय आपराधिक मामलों में न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। याचिका के तहत दायर नामकरण काफी प्रासंगिक नहीं है और यह न्यायालय को अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने से नहीं रोकता है जो अन्यथा उसके पास है, जब तक कि कोई विशेष प्रक्रिया निर्धारित नहीं की जाती है जो अनिवार्य है। यदि किसी मामले में न्यायालय यह पाती है कि अपीलकर्ता अनुच्छेद 226 के तहत अपनी अधिकारिता का आह्वान नहीं कर सकते हैं, तो न्यायालय निश्चित रूप से याचिका को अनुच्छेद 227 या संहिता की धारा 482 के तहत एक याचिका के रूप में मान सकती है।"

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **एस.एन. शर्मा बनाम बिपिन कुमार तिवारी और अन्य** मामले में यह निर्णय दिया है, जो **एआईआर 1970 एससी 786** में प्रकाशित हुआ है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत अधिकारिता का आह्वान कर सकता है, यदि उच्च न्यायालय को विश्वास है कि विवेचना की शक्ति का प्रयोग दुर्भावनापूर्ण तरीके से किया गया है।"

इसलिए, निर्धारित विधि के अनुसार, प्र.सु.प्र. को रद्द करने के लिए जो प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करती है, अनुच्छेद 226/227 के तहत रिट याचिका दायर की जा सकती है। धारा 482 द.प्र.सं. के तहत अधिकारिता का भी आह्वान किया जा सकता है। इसलिए, इस सीमा तक, मुझे उत्तरवादीओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाई गई आपत्ति में कोई सार नहीं मिलता है।

14. डॉ. राजेंद्र सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विवेक तन्खा के साथ, ने तर्क दिया कि प्र.सु.प्र. का एक सरसरी दृष्टि से पढ़ना प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं 13(1)(घ), 13(2), 12 और 15 और भारतीय दंड

संहिता की धाराओं 34 और 120-ख के तहत दंडनीय अपराध के कारित किए जाने का खुलासा नहीं करता है। वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि घटना दिनांक को भी विधायक नव निर्वाचित थे, लेकिन अब तक उन्होंने शपथ नहीं ली थी, इसलिए विधिक रूप से वे लोक सेवक नहीं थे। प्र.सु.प्र. में लगाए गए आरोपों के अनुसार, यह माना जाए कि शिकायतकर्ता श्री विरेंद्र पांडे के निमंत्रण पर याचिकाकर्ता ने उनसे संपर्क किया, लेकिन श्री विरेंद्र पांडे लोक सेवक नहीं होने के कारण, उन्हें रिश्वत देने का प्रश्न भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं 13(1) (घ), 13(2), 12 और 15 की परिभाषा के भीतर नहीं आता है। इसके अलावा, श्री खूंटे और श्री पांडे की बातचीत प्र.सु.प्र. में लगाए गए आरोपों के अनुसार आमंत्रित थी। उन्होंने खुद रिश्वत देने का कोई प्रयास नहीं किया, इसलिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अपराधों को बनाने के लिए आवश्यक तत्व प्र.सु.प्र. में नहीं हैं। जहां तक भारतीय दंड संहिता की धारा 120-ख के तहत अपराध के कारित होने का संबंध है, अपराध निर्मित होने के लिए अवैध कृत्य या गैर-विधिक साधनों द्वारा ऐसा कृत्य जो विधिक न हो, को करने की दो व्यक्तियों के मध्य षडयंत्र होनी चाहिए, ऐसी सहमति को आपराधिक षडयंत्र कहा जाता है। प्र.सु.प्र. में लगाए गए आरोपों के अनुसार श्री खूंटे और श्री विरेंद्र पांडे के बीच बातचीत हुई थी। श्री खूंटे ने श्री पांडे को आश्वासन दिया कि श्री जोगी श्री बालिराम कश्यप के माध्यम से सरकार बनाने में उनकी मदद करेंगे। इसलिए, आपराधिक षडयंत्र बनाने के लिए आवश्यक तत्व इस मामले में अनुपस्थित हैं। याचिकाकर्ता कभी भी आपराधिक षडयंत्र में शामिल नहीं हुआ और न ही कोई आरोप है कि श्री पांडे, श्री बालिराम कश्यप और याचिकाकर्ता आपराधिक षडयंत्र में शामिल थे, बल्कि याचिकाकर्ता को एक मंच प्रबंधित शो में फंसाया गया था। इसलिए, यदि प्र.सु.प्र. को उसके चेहरे के मूल्य पर लिया जाए, तो याचिकाकर्ता द्वारा कोई संज्ञेय अपराध नहीं किया गया है। इसलिए, प्र.सु.प्र. को रद्द किया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. दूसरी ओर, श्री रविश अग्रवाल, महाधिवक्ता और श्री विनय हरित, केंद्रीय शासन के वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्र.सु.प्र. के अनुसार श्री बी.आर. खूंटे, याचिकाकर्ता और उनके पुत्र श्री विरेंद्र पांडे के माध्यम से नव निर्वाचित भाजपा विधायकों को रिश्वत देने की आपराधिक षडयंत्र में शामिल हुए ताकि वे भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर श्री बलिराम कश्यप के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारी का समर्थन करें। उस षडयंत्र के अनुसरण में श्री बी.आर. खूंटे ने श्री विरेंद्र पांडे से संपर्क किया। यहां तक कि याचिकाकर्ता ने श्री विरेंद्र पांडे से टेलीफोन पर संपर्क किया और बाद में वे एक निश्चित स्थान पर मिले, एक वाहन में बैठे और याचिकाकर्ता ने छत्तीसगढ़ राज्य के महामहिम राज्यपाल को संबोधित पत्र सौंपा, जिसमें श्री बलिराम कश्यप के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारी के समर्थन का आश्वासन दिया गया था। याचिकाकर्ता की यह संलिप्तता दिखाती है कि वह षडयंत्र में शामिल था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि जहां तक नव निर्वाचित विधायकों के लोक सेवक नहीं होने का प्रश्न है, चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 66 के अनुसार नव निर्वाचित विधायकों को एक प्रमाण पत्र दिया गया था कि वे राज्य विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने गए हैं और इससे वे विधायक और लोक सेवक बन गए, इसलिए प्रथम दृष्टया अपराध का पता चलता है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि प्रकरण प्रारंभिक चरण में है और न्यायालय को इस तथ्य पर ध्यान देना आवश्यक है कि क्या प्र.सु.प्र. में लगाए गए आरोपों के अनुसार एक संज्ञेय अपराध का पता चलता है और यदि संज्ञेय अपराध का पता चलता है तो पुलिस द.प्र.सं. की धारा 154 के तहत प्र.सु.प्र. दर्ज करने और उसके बाद विवेचना के साथ आगे बढ़ने के लिए बाध्य है। विवेचना एजेंसी साक्ष्य एकत्र करने के चरण में है, इस स्तर पर न्यायालय द्वारा विवेचना में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों को समझने के लिए, यदि हम दंड प्रक्रिया संहिता के प्रासंगिक उपबंधों पर नजर डालें, तो द.प्र.सं. की धारा 2(छ) यह परिभाषित करती है कि "अन्वेषण" में इस संहिता के तहत साक्ष्य एकत्र करने के लिए पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा किए गए सभी कार्यवाही शामिल हैं। यह तब समाप्त होता है जब यह राय बनाई जाती है कि एकत्रित सामग्री के आधार पर, आरोपी को मुकदमे के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने का प्रकरण है और यदि ऐसा है, तो धारा 173 के तहत आरोप पत्र दाखिल करके आवश्यक कदम उठाए जाते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता का अध्याय XII "पुलिस को सूचना और उनकी विवेचना शक्तियों" से संबंधित है। धारा 154 यह निर्धारित करती है कि संज्ञेय अपराध कारित किए जाने से संबंधित हर सूचना, यदि पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को मौखिक रूप से दी जाती है, तो उसे लिखित में दर्ज किया जाएगा और इसका सार ऐसे अधिकारी द्वारा रखी गई पुस्तक में दर्ज किया जाएगा। धारा 156 की उप-धारा (1) यह निर्धारित करती है कि पुलिस स्टेशन का कोई भी प्रभारी अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी भी संज्ञेय अपराध की विवेचना कर सकता है, जिसे उस स्टेशन की स्थानीय क्षेत्राधिकार के भीतर मुकदमा चलाने या विवेचना करने की शक्ति होगी। इस धारा की उप-धारा (2) यह निर्धारित करती है कि किसी भी चरण में पुलिस अधिकारी की कार्यवाही पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है कि यह प्रकरण ऐसा था जिसकी विवेचना करने के लिए इस धारा के तहत अधिकारी को शक्ति नहीं थी।

17. धारा 157 यह निर्धारित करती है कि यदि पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को मिली जानकारी या अन्यथा से "अपराध कारित किए जाने का संदेह करने का कारण" है, जिसकी विवेचना करने के लिए वह धारा 156 के तहत सशक्त है, तो वह व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों में से एक को तथ्यों और परिस्थितियों की विवेचना करने और यदि आवश्यक हो तो अपराधी की खोज और गिरफ्तारी के लिए उपाय करने

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

के लिए नियुक्त करेगा। धारा 160 से 163 पुलिस अधिकारी को अध्याय XII के तहत विवेचना करने के लिए गवाहों की उपस्थिति और उनकी परीक्षा की आवश्यकता के लिए शक्ति प्रदान करती है। धारा 165 और 166 पुलिस अधिकारी को विवेचना करने के लिए तलाशी लेने या तलाशी कराने की शक्ति प्रदान करती है।धारा 169 पुलिस अधिकारी को एक व्यक्ति को हिरासत से रिहा करने का अधिकार देती है यदि अध्याय XII के तहत विवेचना के बाद यह पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को लगता है कि आरोपी को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने के लिए पर्याप्त सबूत या संदेह का उचित आधार नहीं है। धारा 170 पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को आरोपी को सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने या जमानती अपराध के मामले में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने के लिए आरोपी से सुरक्षा लेने का अधिकार देती है, यदि विवेचना के बाद यह लगता है कि ऐसा करने के लिए पर्याप्त सबूत या उचित आधार है। धारा 173 और इसकी उप-धारा (2) यह निर्धारित करती है कि विवेचना पूरी होने के बाद, पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी एक पुलिस रिपोर्ट परंपराध की संज्ञान लेने के लिए सक्षम मजिस्ट्रेट को एक रिपोर्ट भेजेंगे, जिसमें उस उप-धारा के खंड (क) से (च) में सूचीबद्ध मामलों का विवरण होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. दंड प्रक्रिया संहिता का अध्याय XIV "कार्यवाही शुरू करने के लिए आवश्यक शर्तें" से संबंधित है। धारा 190 मजिस्ट्रेट द्वारा अपराधों के संज्ञान से संबंधित है और यह निर्धारित करती है कि एक मजिस्ट्रेट किसी भी अपराध का संज्ञान ले सकता है।दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय XII के प्रावधान दर्शाते हैं कि विस्तृत और व्यापक प्रावधान किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जिस अपराध की सूचना दी गई है, उसकी विवेचना की जाती है और यह विवेचना संहिता के प्रावधानों के अनुसार की जाती है। विवेचना करने का तरीका और विधि पूरी तरह से पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी या उनके द्वारा नियुक्त अधीनस्थ अधिकारी के लिए छोड़ दी गई है। एक मजिस्ट्रेट को इसमें हस्तक्षेप करने की कोई शक्ति नहीं है। धारा 169 और 170 में विचार किए

गए अनुसार यह राय बनाने की शक्ति कि क्या मामले को मजिस्ट्रेट के पास भेजने के लिए पर्याप्त सबूत या संदेह का उचित आधार है या नहीं, पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की है।

19. **महाराजाधिराज बनाम नज़ीर अहमद** मामले में, **जो एआईआर 1945 पीसी 18** में प्रतिवेदित किया गया है, प्रिवी काउंसिल ने यह निर्णय दिया है:

> "भारत में, जैसा कि दिखाया गया है, पुलिस को एक कथित संज्ञेय अपराध की परिस्थितियों की विवेचना करने का एक वैधानिक अधिकार है, बिना किसी न्यायिक प्राधिकरण से अनुमति की आवश्यकता के। और यह एक दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम होगा यदि यह माना जाए कि इन वैधानिक अधिकारों में न्यायालय की अंतर्निहित अधिकारिता के प्रयोग से हस्तक्षेप किया जा सकता है। न्यायपालिका और पुलिस के कार्य पूरक हैं, अतिव्यापी नहीं, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ विधि और व्यवस्था का उचित पालन केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है जब प्रत्येक अपनी कार्य करने की स्वतंत्रता का प्रयोग करे, बेशक, धारा 491 के तहत न्यायालय को हस्तक्षेप करने का अधिकार है जब हेबियस कॉर्पस की प्रकृति में निर्देश देने के लिए कहा जाता है। इस तरह के मामले में, हालांकि, न्यायालय के कार्य तब शुरू होते हैं जब एक आरोप पत्र उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और तब तक नहीं।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

एच.एन. रिशबुड और एस.एन. बसक मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है:

> "दंड प्रक्रिया संहिता के तहत विवेचना में कई पहलू और चरण सम्मिलित हैं, जो अंततः पुलिस द्वारा यह राय बनाने के साथ

समाप्त होते हैं कि क्या एकत्रित सामग्री के आधार पर आरोपी को मुकदमे के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने का प्रकरण है, और आरोप पत्र या अंतिम रिपोर्ट की प्रस्तुति इस राय की प्रकृति पर निर्भर करती है। पुलिस द्वारा इस राय का निर्माण विवेचना का अंतिम चरण है, और यह अंतिम चरण केवल पुलिस द्वारा और किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा नहीं लिया जाना चाहिए।"

20. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **एस.एन. शर्मा बनाम बिपिन कुमार तिवारी और अन्य** मामले में, जो **एआईआर 1970 एससी 786** में प्रतिवेदित किया गया है, यह निर्णय दिया है: "हमें यह प्रतीत होता है कि हालांकि संहिता पुलिस को उन सभी मामलों की विवेचना करने की अप्रतिबंधित शक्ति प्रदान करती है जहां उन्हें संदेह है कि एक संज्ञेय अपराध किया गया है, उचित मामलों में एक पीड़ित व्यक्ति हमेशा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की शक्ति का आह्वान करके अनुतोष मांग सकता है, जिसके तहत यदि उच्च न्यायालय को विश्वास हो जाता है कि पुलिस अधिकारी ने अपनी विवेचना शक्ति का प्रयोग दुर्भावनापूर्ण तरीके से किया है, तो उच्च न्यायालय हमेशा एक पुलिस अधिकारी को उसके विधिक अधिकारों के दुरुपयोग से रोकने के लिए एक परमादेश रिट जारी कर सकता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. **पश्चिम बंगाल बनाम स्वपन कुमार गुहा** मामले में, जो **एआईआर 1982 एससी 949** में प्रतिवेदित किया गया है, माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रचूड़ ने न्यायमूर्ति ए.पी. सेन के निर्णय से सहमति व्यक्त करते हुए कहा है, जिसमें न्यायमूर्ति वर्धराजन ने भी सहमति व्यक्त की है: "यदि प्र.सु.प्र. में संज्ञेय अपराध कारित किए जाने का खुलासा नहीं होता है, तो न्यायालय को उस सूचना के आधार पर विवेचना को रद्द करने का अधिकार होगा।" माननीय न्यायमूर्ति ए.पी. सेन ने उस मामले में मुख्य निर्णय लिखा है, जिसमें चंद्रचूड़

मुख्य न्यायाधीश और वर्धराजन न्यायमूर्ति ने सहमति व्यक्त की है, उन्होंने निम्नलिखित विधिक स्थिति निर्धारित की है:

".....विधिक स्थिति अच्छी तरह से निर्धारित है। विधिक स्थिति यह प्रतीत होती है कि यदि एक अपराध का खुलासा होता है, तो न्यायालय सामान्य रूप से मामले की विवेचना में हस्तक्षेप नहीं करेगी और कथित अपराध की विवेचना की अनुमति देगी; यदि, हालांकि, सामग्री अपराध का खुलासा नहीं करती है, तो सामान्य रूप से विवेचना की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।"

फिर से **माधवराव जिवाजी राव शिंदे बनाम संभाजीराव चंद्रोजीराव आंग्रे** मामले में, जो **एआईआर 1988 एससी 709** में प्रतिवेदित किया गया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है: "विधिक स्थिति अच्छी तरह से निर्धारित है कि जब एक मुकदमे को प्रारंभिक चरण में रद्द करने के लिए कहा जाता है, तो न्यायालय द्वारा लागू किया जाने वाला परीक्षण यह है कि क्या विवादित आरोप प्रथम दृष्टया अपराध स्थापित करते हैं। यह भी न्यायालय के लिए विशेष विशेषताओं पर विचार करना है जो एक विशेष मामले में दिखाई देती हैं, यह तय करने के लिए कि क्या मुकदमे को जारी रखने की अनुमति देना समीचीन और न्याय के हित में है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **बिहार राज्य बनाम मुराद अली खान** मामले में, जो **एआईआर 1989 एससी 1** में प्रतिवेदित किया गया है, यह कहा है:

> "धारा 482 के तहत अधिकारिता का प्रयोग संयम और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए और यह निर्धारित किया है कि इस अधिकारिता का प्रयोग करते समय, उच्च न्यायालय को इस बात की विवेचना नहीं करनी चाहिए कि शिकायत में लगाए गए आरोप साक्ष्य द्वारा स्थापित होने की

संभावना है या नहीं।" **भजन लाल के मामले** (पूर्वोक्त) में भी, निर्णय के कंडिका 108 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 7 श्रेणियों को निर्धारित किया है जहां न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 या द.प्र.सं. की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग कर सकती है और उन सात श्रेणियों में से वर्तमान मामले में प्रासंगिक श्रेणियां हैं: (i) "जहां प्रथम सूचना प्रतिवेदन या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके चेहरे के मूल्य पर लिया जाए और पूरी तरह से स्वीकार किया जाए, प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनाते हैं या आरोपी के खिलाफ प्रकरण नहीं बनाते हैं।" (ii) "जहां प्रथम सूचना प्रतिवेदन और अन्य सामग्री, यदि कोई हो, जो प्र.सु.प्र. के साथ है, एक संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करती है, जो पुलिस अधिकारियों द्वारा धारा 156(1) के तहत विवेचना को उचित ठहराती है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **हरियाणा राज्य और अन्य बनाम चौधरी भजन लाल और अन्य** पूर्वोक्त के मामले में, जो कंडिका 31 में अभिनिर्धारित किया गया है कि "सभी संहिताओं का एक विस्तृत अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज करने के लिए एक आवश्यक शर्त यह है कि एक सूचना होनी चाहिए और उस सूचना में एक संज्ञेय अपराध का खुलासा होना चाहिए। यदि कोई सूचना जिसमें एक संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है, धारा 154(1) की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाती है, तो उस पुलिस अधिकारी के पास ऐसी सूचना के आधार पर एक प्रकरण दर्ज करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। और यह निर्णय में आगे यह भी कहा गया है कि धारा 157 के तहत एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को, जो प्राप्त जानकारी या अन्यथा से एक अपराध कारित किए जाने का संदेह करने का कारण है - अर्थात् एक संज्ञेय

अपराध, उसे व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ने या अपने किसी अधीनस्थ अधिकारी को तथ्यों और परिस्थितियों की विवेचना करने और यदि आवश्यक हो तो अपराधी की खोज और गिरफ्तारी के लिए उपाय करने के लिए नियुक्त करना आवश्यक है। धारा 157 की उप-धारा (2) के अनुसार पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजने की आवश्यकता है और धारा 157(1) के प्रावधानों के अनुसार एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी भी संज्ञेय मामले की विवेचना कर सकते हैं। और इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि "संदेह करने का कारण" प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों द्वारा शासित और निर्धारित किया जाना चाहिए और उस चरण में प्रथम सूचना प्रतिवेदन में लगाए गए तथ्यों के पर्याप्त प्रमाण का प्रश्न नहीं उठता है और संहिता की धारा 157(1) के तहत विवेचना शुरू करने की पूर्व शर्त एक संज्ञेय अपराध कारित किए जाने के संदेह का कारण का अस्तित्व है जो धारा 154(1) के तहत पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत पहली सूचना में लगाए गए आरोपों द्वारा प्रथम दृष्टया प्रकट होना चाहिए। कंडिका 54 में यह निर्णय दिया गया है कि एक पुलिस अधिकारी द्वारा विवेचना का प्रारंभ दो शर्तों के अधीन है, पहला, पुलिस अधिकारी को धारा 157(1) के तहत आवश्यकतानुसार एक संज्ञेय अपराध कारित किए जाने का संदेह करने का कारण होना चाहिए और दूसरा, पुलिस अधिकारी को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में विवेचना शुरू करने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि क्या विवेचना शुरू करने के लिए पर्याप्त आधार है, जैसा कि धारा 157(1) के परंतुक के खंड (ख) में विचार किया गया है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. फिर से, **(1999)3 सुप्रीम कोर्ट** केसेस **259** में प्रतिवेदित माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **राजेश बजाज बनाम एनसीटी दिल्ली राज्य व अन्य** मामले में, यह निर्णय दिया है: "यह आवश्यक नहीं है कि एक शिकायतकर्ता अपने शिकायत के शरीर में आरोपित अपराध के सभी तत्वों को शब्दशः पुनरुत्पादित करे। न ही यह आवश्यक है कि शिकायतकर्ता इतने शब्दों में कहे कि आरोपी का

उद्देश्य अपमानजनक या धोखाधड़ी वाला था। अपराध की परिभाषा को विभिन्न घटकों में विभाजित करना और यह सूक्ष्म विवेचना करना कि क्या सभी तत्वों को शिकायत में सटीक रूप से निर्दिष्ट किया गया है, इस स्तर पर आवश्यकता नहीं है। यदि अपराध के लिए तथ्यात्मक आधार शिकायत में रखा गया है, तो न्यायालय को विवेचना के चरण के दौरान केवल इस आधार पर आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की जल्दी नहीं करनी चाहिए कि एक या दो तत्वों को विस्तार से नहीं बताया गया है। प्र.सु.प्र. को रद्द करने के लिए (एक कदम जो केवल अत्यधिक दुर्लभ मामलों में अनुमति दी जाती है) शिकायत में जानकारी इतनी बुनियादी तथ्यों से रहित होनी चाहिए जो अपराध बनाने के लिए बिल्कुल आवश्यक हैं।" इसी तरह का दृष्टिकोण माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **जे. टी. (सल्प. 1) एस. सी. 412** में प्रतिवेदित **एम. नारायणदास बनाम कर्नाटक राज्य व अन्य** मामले में लिया है, कंडिका 33 में यह अभिनिर्धारित किया गया है: "यह स्पष्ट है कि यदि कोई सूचना जिसमें एक संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है, धारा 154(1) की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाती है, तो उस पुलिस अधिकारी के पास ऐसी सूचना के आधार पर एक प्रकरण दर्ज करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है और किसी भी संज्ञेय अपराध के अन्वेषण का क्षेत्र विशेष रूप से विवेचना एजेंसियों के कार्यक्षेत्र में है, जिस पर न्यायालयों का कोई नियंत्रण नहीं है और विवेचना में कार्यवाही को रोकने या बाधित करने की कोई शक्ति नहीं है, जब तक कि अन्वेषण प्रावधानों के अनुसार आगे बढ़ता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **भारत संघ बनाम प्रकाश पी. हिंदुजा और अन्य** मामले में, जो **जेटी 2003 (5) एससी 300** में प्रतिवेदित किया गया है, कंडिका 18 और 19 में यह निर्णय दिया है:

> "अपराध अनुसंधान और अपराध दंड के क्षेत्र में एक स्पष्ट और अच्छी तरह से परिभाषित कार्य क्षेत्र है। अपराध की विवेचना

का क्षेत्र विशेष रूप से पुलिस विभाग के माध्यम से कार्यपालिका के लिए आरक्षित है, जिस पर राज्य सरकार का अधीक्षण है। कार्यपालिका जो विधि और व्यवस्था की स्थिति पर नजर रखने के लिए जिम्मेदार है, अपराध को रोकने के लिए बाध्य है और यदि एक अपराध का आरोप लगाया जाता है तो इसकी विवेचना करना और अपराधी को न्याय के सामने लाना इसका कर्तव्य है। एक बार जब यह विवेचना करता है और एक अपराध का पता चलता है तो इसका कर्तव्य है साक्ष्य एकत्र करना ताकि अपराध को साबित किया जा सके। एक बार जब यह पूरा हो जाता है और विवेचना अधिकारी न्यायालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है जिसमें अपराध के संज्ञान के लिए अनुरोध किया जाता है, तो इसका कर्तव्य समाप्त हो जाता है। न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लेने के बाद पुलिस का विवेचना कार्य समाप्त हो जाता है, सिवाय धारा 173(8) में निहित प्रावधान के। तब न्यायपालिका का निर्णयात्मक कार्य शुरू होता है जो यह निर्धारित करने के लिए है कि क्या अपराध किया गया है और यदि ऐसा है तो क्या पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में आरोपित व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किया गया है और अपराध के लिए विधि के अनुसार पर्याप्त दंड देना है। इस प्रकार अपराध अनुसंधान और उसके बाद के निर्णय के क्षेत्र में पुलिस और मजिस्ट्रेट के बीच एक अच्छी तरह से परिभाषित और अच्छी तरह से सीमांकित कार्य है। यह किंग **एम्परर बनाम ख्वाजा नज़ीर अहमद (एआईआर 1945 पीसी 18)** में मान्यता प्राप्त है, जहां प्रिवी काउंसिल ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

.....

कंडिका 26 में यह देखा गया कि एक संज्ञेय अपराध में विवेचना करने की पुलिस की शक्ति आमतौर पर न्यायपालिका द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

"विधिक स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा भी निर्धारित की गई है कि न्यायालय विवेचना में हस्तक्षेप नहीं करेगी या विवेचना के दौरान जो प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज करने के समय से लेकर धारा 173(2) के तहत पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत करने तक का समय है, यह क्षेत्र विशेष रूप से विवेचना एजेंसी के लिए आरक्षित है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26. फिर से, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **पुलिस अधीक्षक, सीबीआई और अन्य बनाम तपन कुमार सिंह** मामले में, जो **(2003) 6 सर्वोच्च न्यायालय** के **मामलों** में **175** में प्रतिवेदित किया गया है, यह निर्णय दिया है: "जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि दी गई सूचना में एक संज्ञेय अपराध कारित किए जाने का खुलासा होना चाहिए और इस तरह की सूचना पुलिस अधिकारी को एक संज्ञेय अपराध कारित किए जाने का संदेह करने का आधार प्रदान करना चाहिए। इस स्तर पर यह पर्याप्त है यदि पुलिस अधिकारी दी गई सूचना के आधार पर एक संज्ञेय अपराध कारित किए जाने का संदेह करता है, न कि उसे यकीन या संतुष्ट होना चाहिए कि एक संज्ञेय अपराध किया गया है। यदि उसे प्राप्त सूचना के आधार पर संदेह करने का कारण है कि एक संज्ञेय अपराध किया गया हो सकता है, तो उसे सूचना दर्ज करनी चाहिए और विवेचना करनी चाहिए। इस स्तर पर यह भी आवश्यक नहीं है कि वह सूचना की सत्यता के बारे में खुद को संतुष्ट करे। यह केवल एक पूर्ण विवेचना के बाद है कि वह सूचना की सत्यता या अन्यथा पर रिपोर्ट करने में सक्षम हो सकता है। इसी तरह, भले ही सूचना सभी विवरण प्रदान न करे, उसे विवेचना के दौरान उन

विवरणों का पता लगाना चाहिए और सभी आवश्यक साक्ष्य एकत्र करना चाहिए। दी गई सूचना जो एक संज्ञेय अपराध कारित किए जाने का खुलासा करती है, केवल विवेचना मशीनरी को गति में लाती है, ताकि सभी आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए जा सकें और उसके बाद विधि के अनुसार कार्रवाई की जा सके। सच्चा परीक्षण यह है कि क्या दी गई सूचना एक संज्ञेय अपराध कारित किए जाने का संदेह करने का कारण प्रदान करती है, जिसे पुलिस अधिकारी धारा 156 के तहत विवेचना करने के लिए सशक्त है। यदि यह करता है, तो उसके पास सूचना दर्ज करने और मामले की विवेचना करने या किसी अन्य सक्षम अधिकारी को विवेचना करने के लिए नियुक्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यह प्रश्न कि क्या रिपोर्ट सही है, क्या यह घटना के तरीके के बारे में पूरी जानकारी देती है, क्या आरोपी का नाम है, और क्या आरोपों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं, ये सभी ऐसे मामले हैं जो इस प्रश्न के विचार से अलग हैं कि क्या रिपोर्ट एक संज्ञेय अपराध कारित किए जाने का खुलासा करती है। भले ही सूचना इन मामलों के बारे में पूरी जानकारी न दे, विवेचना अधिकारी अपने कर्तव्य से मुक्त नहीं है कि वह मामले की विवेचना करे और सच्चे तथ्यों का पता लगाए, यदि वह कर सकता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

27. **मध्य प्रदेश राज्य बनाम अवध किशोर गुप्ता और अन्य** मामले में, जो **जेटी 2003 (9) एससी 284** में प्रतिवेदित किया गया है, कंडिका 11 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है:

"उच्च न्यायालय के पास धारा 482 के तहत बहुत व्यापक शक्तियां हैं और शक्ति की बहुतायत के लिए इसके प्रयोग में बहुत सावधानी की आवश्यकता है। न्यायालय को सावधानी से देखना चाहिए कि इसका निर्णय इस शक्ति के प्रयोग में ठोस सिद्धांतों पर आधारित है। अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग वैध अभियोजन को दबाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय, जो एक राज्य की

सर्वोच्च न्यायालय है, को सामान्य रूप से एक मामले में प्रथम दृष्टया निर्णय देने से बचना चाहिए जहां तथ्य अधूरे और अस्पष्ट हैं और अधिकांश साक्ष्य एकत्र और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए हैं और शामिल मुद्दे, चाहे तथ्यात्मक हों या विधिक, विशाल हैं और पर्याप्त सामग्री के बिना उनके सही परिप्रेक्ष्य में नहीं देखे जा सकते हैं। बेशक, किसी भी चरण में कार्यवाही को रद्द करने के लिए अपनी असाधारण अधिकारिता का प्रयोग करने वाले मामलों के संबंध में कोई कठिन और तेज नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है। यह उचित नहीं होगा कि उच्च न्यायालय शिकायत के मामले का विश्लेषण सभी संभावनाओं के प्रकाश में करे ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि दोषसिद्धि कायम रहेगी और ऐसे परिसर पर यह निष्कर्ष निकाला जाए कि कार्यवाही को रद्द किया जाना चाहिए। यह गलत होगा कि उसके सामने सामग्री का आकलन किया जाए और निष्कर्ष निकाला जाए कि शिकायत पर आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। शिकायत पर स्थापित कार्यवाही में, कार्यवाही को रद्द करने के लिए अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग केवल उस मामले में किया जाना चाहिए जहां शिकायत किसी अपराध का खुलासा नहीं करती है या तुच्छ, उत्पीड़क या दमनकारी है। यदि शिकायत में लगाए गए आरोप उस अपराध का निर्माण नहीं करते हैं जिसका संज्ञान मजिस्ट्रेट ने लिया है, तो धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग से इसे रद्द करना खुला है। हालांकि, यह आवश्यक नहीं है कि दोषसिद्धि या बरी होने के लिए मामले का सूक्ष्म विश्लेषण किया जाए। शिकायत को एक पूरे के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। यदि यह शिकायत में आरोपों के विचार से और शिकायतकर्ता के शपथ के बयान के प्रकाश में प्रतीत होता है कि अपराध के तत्व या अपराधों का खुलासा होता है और शिकायत को दुर्भावनापूर्ण, तुच्छ या उत्पीड़क दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं है, तो उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं होगा। जब एक पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज की जाती है और एक अपराध दर्ज किया जाता है, तो सूचनाकर्ता की दुर्भावना गौण महत्व की होगी। यह विवेचना के दौरान एकत्र की गई सामग्री और न्यायालय में पेश किए गए साक्ष्य हैं जो

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आरोपी व्यक्ति के भाग्य का फैसला करते हैं। सूचनाकर्ता के खिलाफ दुर्भावना के आरोप स्वयं कार्यवाही को रद्द करने का आधार नहीं हो सकते हैं।"

28. इसलिए, पूर्वोक्त विभिन्न निर्णयों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि के दृष्टिकोण से, इस स्तर पर, जबकि याचिकाकर्ता के मामले पर विचार किया जा रहा है कि प्र.सु.प्र. को रद्द किया जाए या नहीं, न्यायालय को यह देखना आवश्यक है कि क्या प्र.सु.प्र. में आरोपित तथ्यों को उनके चेहरे के मूल्य पर लिया जाए और पूरी तरह से स्वीकार किया जाए, तो क्या वे प्रथम दृष्टया कोई अपराध बनाते हैं या आरोपी के खिलाफ प्रकरण बनाते हैं। यदि प्र.सु.प्र. में उल्लिखित तथ्य प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध का खुलासा करते हैं, तो इस न्यायालय को आरोपित तथ्यों की सत्यता, विश्वसनीयता, पर्याप्तता और पर्याप्त प्रमाण की विवेचना करने और सूक्ष्म विवेचना करने की आवश्यकता नहीं है और क्या सभी तत्वों को शिकायत में सटीक रूप से निर्दिष्ट किया गया है, यह इस स्तर पर आवश्यकता नहीं है। यदि अपराध के लिए तथ्यात्मक आधार शिकायत में रखा गया है, तो न्यायालय को विवेचना के चरण के दौरान आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की जल्दी नहीं करनी चाहिए, केवल इस आधार पर कि एक या दो तत्वों को विस्तार से नहीं बताया गया है। यदि सभी शर्तें संतुष्ट हैं, तो अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग वैध अभियोजन को दबाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय, जो एक राज्य की सर्वोच्च न्यायालय है, को सामान्य रूप से एक मामले में प्रथम दृष्टया निर्णय देने से बचना चाहिए जहां तथ्य अधूरे और अस्पष्ट हैं और अधिकांश साक्ष्य एकत्र और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए हैं और शामिल मुद्दे, चाहे तथ्यात्मक हों या विधिक, विशाल हैं और पर्याप्त सामग्री के बिना उनके सही परिप्रेक्ष्य में नहीं देखे जा सकते हैं। **मुर्फी अली खान** के मामले में (पूर्वोक्त), माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि न्यायालय को शक्ति का प्रयोग संयम और सावधानी के साथ करना चाहिए और यह निर्धारित किया है कि इस अधिकारिता का प्रयोग करते समय, उच्च न्यायालय को इस बात की विवेचना नहीं करनी चाहिए कि

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

शिकायत में लगाए गए आरोप साक्ष्य द्वारा स्थापित होने की संभावना है या नहीं। न्यायालय को अपने अधिकारिता का प्रयोग केवल दुर्लभ मामलों में करना है, जब न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्र.सु.प्र. में आरोपों के आधार पर कोई प्रथम दृष्टया अपराध नहीं बनता है और यदि विवेचना जारी रखने की अनुमति दी जाती है, तो इससे न्याय की विफलता होगी।

29. इसलिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों और निर्धारित सिद्धांतों के प्रकाश में, यदि हम वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता और दो अन्य व्यक्तियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को देखें और प्र.सु.प्र. में नामित अन्य व्यक्तियों के साथ याचिकाकर्ता की भूमिका के अनुसार, कुछ व्यक्तियों के साथ एकांत स्थान पर बैठक, फोन पर बातचीत, पत्र देना और एक विशेष व्यक्ति के समर्थन का आश्वासन देना जो उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित करने के लिए है, प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराधों के आयोग के संदेह का कारण बताता है। इस स्तर पर, किसी भी राय को व्यक्त करना और किसी निष्कर्ष पर पहुंचना आवश्यक नहीं है और इस स्तर पर कोई आदेश पारित करना विवेचना एजेंसी के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने के समान होगा और उन्हें साक्ष्य एकत्र करने और अपनी अंतिम राय बनाने के लिए सभी निष्पक्षता के साथ जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए, जैसा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 169 और 170 में कल्पना की गई है। इसलिए, मैं राय रखता हूं कि याचिकाकर्ता इस न्यायालय के असाधारण अधिकारिता को लागू करने के लिए एक प्रकरण बनाने में सफल नहीं हुआ है जो प्र.सु.प्र. को रद्द करने के लिए पर्याप्त होगा।

30. जहां तक सीखे हुए वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा तर्क के दौरान व्यक्त की गई चिंता का संबंध है, विवेचना में जानबूझकर देरी के बारे में जो याचिकाकर्ता के लिए हानिकारक हो सकती है, सीखे हुए वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आशंकाएं हैं कि विवेचना एजेंसी विवेचना में देरी कर सकती है और ऐसे चरण पर निष्कर्ष निकाल सकती है जो याचिकाकर्ता को अजीब स्थिति में डाल सकता है। इस

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

संबंध में भी, मुझे विवेचना एजेंसी की निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा पर संदेह करने का कोई कारण नहीं मिलता है, क्योंकि वर्तमान विवेचना एजेंसी देश की सर्वोच्च और प्रमुख विवेचना एजेंसी है और अब तक देश के हर नागरिक को वर्तमान विवेचना एजेंसी पर उच्च आशाएं और पूरा विश्वास है। हालांकि, याचिकाकर्ता के लिए सीखे हुए वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा उठाए गए संदेहों को दूर करने के लिए, यह अपेक्षित है कि विवेचना एजेंसी विधि के अनुसार अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए विवेचना को तेजी से आगे बढ़ाए।

31. परिणामस्वरूप, मुझे इस स्तर पर प्र.सु.प्र. को रद्द करने के लिए अनुच्छेद 226/227 के तहत असाधारण अधिकारिता को लागू करने का कोई कारण नहीं मिलता है, क्योंकि विवेचना अभी भी प्रारंभिक चरण में है। इसलिए, याचिका खारिज किए जाने योग्य है और इसे खारिज किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षर/-
एल.सी. भादू,
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated by Ajey kumar